भारत में नक्सलवाद एक चुनौती

*डॉ. (श्रीमती) संघमित्रा दुधे

स्वतंत्रता के बाद भारत ने बाह्य एवं आंतरिक क्षेत्र में सफलताएं अर्जित की है किंतु आंतरिक विकास के क्षेत्र में कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई जिससे आज एक बड़ी समस्या के रूप में सामना करना पड़ रहा है, वह है देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला। विकास की दौड़ में चलते हुए देश के कुछ हिस्सों ने अपने आपको उपेक्षित सा महसूस किया। 8 प्रतिशत से ऊपर की विकास दर के साथ सरपट भागती अर्थ व्यवस्था के दौर में इन उपेक्षित हिस्सों के लोगों ने सरकार के विरूद्ध अपने हाथों में हथियार उठा लिए और नक्सलवाद जैसा एक शासन विरोधी उग्र आंदोलन का जन्म हो गया। यह नक्सलवाद अब तक हजारों लोागों की जान ले चुका है। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक सूत्र भारत, नेपाल और स्वंत्रता के पूर्व के पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नक्सलवाड़ी गाँव से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम 1967 में यहां के आदिवासियों ने भूस्वामियो के विरूध विद्रोह कर दिया था। इसके बाद इसी तर्ज पर यह आंदोलन बड़ी तेजी के साथ देश के अन्य हिस्सों में फैलता चला गया अपने आपको बुद्धिजीवी वर्ग कहलाने वाले युवाओं ने इस आंदोलन से जुड़कर एक नई समानतावादी समाजवादी व्यवस्था के सपने संजोए। क्योंकि स्वतंत्रता के दो दशक बीत जाने के बाद भी भारत के राज्यों का एक बड़ा तबका जिनमें कृषक, श्रमिक व आदिवासी थें। वह शासकीय नीतियों व सामाजिक शोषण का शिकार हो रहा था इस वर्ग का मानना था कि सशक्त क्रंाति के द्वारा ही सामन्त वर्ग और स्वार्थ पूर्ण सत्ता से अपने अधिकारो के लिए लड़ा जा सकता है। सर्वप्रथम अंजाम दिया नक्सलवादी के तीर कमान वाली संथाल जाति ने।एक खूनी संघर्ष में जमीन पर मालिकाना हक जमाते हुए अन्न के जमादारों कों लूट कर उनका माल गरीब जनता में लुटा दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस कार्यवाही कर के आंदोलन को दबा दिया पर नक्सलवादियों का यह आंदोलन सत्ता द्वारा शोषितों व गरीबों दलितों को राह बता गया । यह ''उच्चस्तर के वर्ग संघर्ष और छापा मार युद्ध'' की शुरुआत माना गया। इस आंदोलन के नेता चारू मजुमदार का मानना था कि–''भारत का हर कोना ज्वालामुखी बन चुका है।'' 1970 के मध्य और 1971 के बीच यह हिंसात्मक आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था । ऐसा माना जाता है कि देश भर में 4000 झडपे नक्सलवादियों व पुलिस के मध्य हुई । भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों को एक नई शक्ति के उभरने का संकेत हुआ । इस आंदोलन की कार्यशैली से भारत सरकार को कानून, व्यवस्था व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खतरे का आभास हुआ। सरकार ने आप्रेशन ''स्टीपलचेप'' के नाम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में 1 जुलाई से 15अगस्त 1971 तक एक अभियान की शुरूआत की जिसमें संदिग्ध नक्सलवादियों कों गिरफ्तार कर उससे उनके हथियार व विस्फोटक सामग्री जब्त कर ली जाती थी । इस अभियान में पश्चिम बंगाल को सफलता मिली चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया । कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गयी। और पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे नक्सलवादी आंदोलन ने दम तोड़ दिया । थोड़े समय बाद ही 1980 में आंध्रप्रदेश में कोंडापल्ली सीतारम्मैया के नेतृत्व में पीपुल्स वार ग्रुप का गठन हुआ । और यह आंदोलन पुनः सक्रिय हो गया । इसके क्रांतिकारी आंदोलन में निम्न बातों पर जोर दिया गया–

1. भूमि का गरीबों को पुनर्वितरण ।
2. खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलवाना ।
3. कर जुर्माना लगाना।
4. जन अदालतों का चलन ।
5. सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना ।
6. सरकारी कर्मचारियों काअपहरण करना ।
7. पुलिस कर्मियों पर हमला करना ।
8. अपनी तरफ से सामाजिक संहिता लागू करना ।

उपेक्षित वर्ग में आशा का संचार हुआ। उन्हे नक्सलवादियों पर विश्वास हुआ। इनके रूप में गरीबों के हितों को पहचानने वाली सामानान्तर सरकार स्थापित हो गयी । साहित्यिक व सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से ये संगठन (नक्सलवादी) अपनी बात जनसामान्य तक पंहुचाने और समर्थन पाने में सफल हो गया । धीरे धीरे इस संगठन का प्रभाव महाराष्ट्र मध्यप्रदेश और उड़ीसा पर पडने लगा । संगठन की गूंज कर्नाटक व तमिलनाडू तक सुनाई देने लगीं। आंध्रप्रदेश सरकार ने 1992 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और आंध्रप्रदेश पुलिस केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल की सहायता से इसका दमन कर दिया। कोंडापल्ली सीतारम्मैया व अन्य संगठन नेताओं की गिरफ्तारी से नक्सलवादियों में हताशा आ गई और करीब 8000 से ज्यादा नक्सलवादीयों से अधिकारीयों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बिहार में भी नक्सलवादी आंदोलनव अपने हिंसा तक रूप में सक्रिय हो गया था। कुछ जगह पर एम सी सी नाम से इस आंदोलन का संगठन अपनी सामानान्तर अदालतें चलाता था। जहां अभियुक्तों का सिर कलम कर दिया जाता था। भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय ने माना है कि 9 राज्यों के 16 जिलों में नक्सलवादी आंदोलन अपनी जड़े जमा चुका है आंध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उडीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री ने नक्सलवादियों के बढ़तें हुए प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए माना कि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। ''संघर्ष प्रबंधन संस्थान '' के अनुसार यह आंदोलन 14 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है।

नक्सलवादियों की हिंसात्मक प्रवृत्ति में इजाफा हुआ है । उनके पास बहुतायत मात्रा में नवीनतम टेक्नालॉजी के हथियारों का खजाना है । भारत सरकार के एक सरकारी सर्वेक्षण के दौरान वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक नक्सलवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक घटनाओं का स्वरूप कुछ इस तरह है–

* प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा

केन्द्रीय गृहमंत्रालय के एक सर्वे के अनुसार देश में वर्ष 2003 में 1597 नक्सलवादी घटनाएँ हुई जिनमें पुलिस के 105 कर्मचारी, 410 नागरिक एवं 216 नक्सली मारे गए इस तरह कुल 731 मौतें हुई । वर्ष 2004 में 1,533 नक्सली घटनाओं में 100 पुलिस कर्मचारी, 466 नागरिक एवं 87 नक्सली मारे गए । इस तरह कुल 653 मौतें हुई । वर्ष 2005 में 1608 नक्सली घटनाओं में 153 पुलिस कर्मचारी, 524 नागरिक एवं 255 नक्सली मारे गए । इस वर्ष मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या ज्यादा थी । कुल 902 लोग मारे गए। वर्ष 2006 में 1509 घटनाओं में 157 पुलिस, 521 नागरिक एवं 272 नक्सली मारे गए । इस वर्ष मारे गए नक्सलियों का प्रतिशत ज्यादा था । कुल 950 लोग मारे गए। वर्ष 2007 में 842 घटनाओं में 138 पुलिस कर्मचारी, 220 नागरिक एवं 93 नक्सली इस तरह कुल 451 लोग मारे गए । वर्ष 2007 में सरकारों के उदारवादी, सहयोगात्मक एवं विकासशील नीतियों के चलते नक्सली घटनाओं और फलस्वरूप होने वाली मौतों में कमी आई ।

NRrhlx< o e/;in'k e uDlyokn&उग्रवादियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है । नक्सलवादी वहां अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं इस बात को वहां के गृहमंत्री स्वयं स्वीकार कर चूके है । यहां के आदिवासी माओवादियों को दादा कहते । जो यहां की समामाकि व्यवस्था मे ंअपना कानून चलाते हैं । नेताओं और सुरक्षाकर्मियों के विरोध के लिए माओवादी जमीनी सुंरगो और प्रेशर बमों का खुलकर प्रयोग कर रहें। पी एल जी ए संगठन पुरूषों की तरह महिलाओं की भर्ती कर रहा है उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें छापामार दस्तों की अगुवाई के लिए जिम्मेदारी सौप रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादियों के बढते हुए प्रभाव को कम कम करने के लिए सलवा जुडूम नामक संगठन को समर्थन दिया है । मुख्यमंत्री रमनसिंह नें मू.पू. वामपंथी और अब विपक्ष के नेता महेन्द्र कर्मा के विचार को मान्यता देते हुए जनता को हथियारों से लैंस होना चाहिए को मान्यता दी हैं इसी तर्ज पर सलवा जुडूम (शांति सेना) को राइफल व मशीन गन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं परंतु इससे भी कोई हल निकलता प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि नक्सलवादी इन जुडूम कार्यकर्ताओं की निर्ममता से हत्या कर रहे हैं। दिसंबर 2007 में दंतेवाड़ा में 12 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया। दंतेवाड़ा देश के आठ सबसे अधिक अंशात जिलों में से एक है जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में तुंरत विकास परियोजनाओं के लिये चुना है। लेकिन राहुलसिंह का कहना हैं–''Vdjko dk lkFk fodkl ugh gks ldrk ;gks rks rjr i.k ;k) dh t:jr gS ftl dk ckjs e vf/kdkfj;ks dk vHkh rd Hkku ugh gSA'' छत्तीसगढ़ का सुरक्षा ढांचा काफी कमजोर है राष्ट्रीय औसतन 100 वर्ग कि.मी. पर 54 पुलिसकर्मी है। दूर दराज के थाने टेलिफोन सुविधा से वंचित है । पुलिस महकमें के लिये आंबटित `राशि जो उनके आधुनिकरण, सशस्त्रीकरण के लिए निश्चित की गई थी वह उन पर खर्च नहीं की गई या अन्य योजनाओं में सरकार द्वारा लगा दी गई है । फलतः

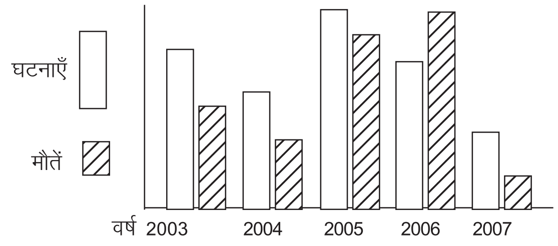

मावोवादी पुलिस कर्मियों की निर्मिम हत्यायें कर रहे हैं । मुख्यमंत्री रमनसिंह ने हारकर अपने प्रदेश की नक्सलवादी समस्या को राष्ट्रीय समस्या करार दे दिया है । मध्यप्रदेश में भी नक्सलवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं । मण्डला, बालाघाट व छत्तीसगढ़ से लगे क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियां सक्रिय है । देश भर में एक अनुमान के तहत विगत चार वर्षो में नक्सलवादी संगठनों ने 25 अरब रूपयों से अधिक की सरकारी व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। नक्सलवादी समस्या से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों की नीतियों में तादात्मय होना भी आवश्यक है, क्योंकि नक्सलवाद एक स्थानीय क्षेत्रीय समस्या है जब तक केन्द्र व राज्य समन्वयकारी और सहयोग रवैया नहीं अपनाएंगे तब तक सफलता हासिल नहीं की जा सकती। आन्ध्रप्रदेश में नक्सलवादियों के मंसूबों को विफल करने की रणनीति प्रभावी साबित हुई है। इसके लिए वहां की सरकार ने अपनी विशेष गुप्तचर व्यवस्था का सहारा लिया है । इसके साथ ही उग्रवादियों के साथ ही नक्सलवादियों के छिपने के ठिकानों में ''ग्रेहाउंडस'' नामक नए कंमाडों बल्कि त्वरित तैनाती और इसके भी बढ़कर न्यूनतम राजनैतिक हस्तक्षेत्र के माध्यम से सफलता हासिल की है। भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ नक्सलवादियों का पकड़ा जाना इस बात का संकेत है कि नक्सलवादी अपने आपको आधुनिकतम शस्त्रों से लैस कर रहे हैं। उनके एल.टी.टी.ई. के साथ मजबूत संबंध है, ताजा जानकारी है कि दार्जिलिंग में एक नए ठिकानों से इस संगठन ने नए सिरे से फिर काम शुरू करना प्रारंभ कर दिया है । असम के उल्फा संगठन से रिश्ता जोड़ा है इस तरह की जानकाररिया ये संकेत दे रही है कि संघर्ष फैलाने के लिए ये नई–नई योजनाएं बना रहे हैं । नक्सलवाद ग्रस्त राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपने–अपने राज्य के विकासात्मक पहलुओं पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं । छत्तीसगढ़, म.प्र., झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश जैसे अन्य राज्य जो नक्सली गतिविधियों के गढ़ बन गए हैं वहां के राजनीतिज्ञों, प्रशासकों व मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत रूचि लेकर नक्सली हिंसा दसे निपटने हेतु संभावित उपयों को हाथ में लेना चाहिए । प्रदशों की पुलिस व्यवस्था को पर्याप्त व संवेदनशील बनाना होगा । क्योंकि आज ये ही सर्वप्रथम नक्सली हिंसा का शिकार हो रही है । पुलिस व्यवस्था को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से युक्त हथियारों से भी लैस करना होगा । इन सब प्रयासों के अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य अपनी नीतियों में सामाजिक समानता एवं विकास की प्रक्रिया को महत्व दें । योजनाओं को स्पष्ट व सार्थक स्वरूप प्रदान करें । गरीबी पिछड़ेपन व बेरोजगारी दूर करने के प्रयास तेज करें शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा, सम्मान एवं बड़े पैमाने पर निजी निवेश और विकेन्द्रित उद्यम को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण का निर्माण करें। कुल मिलाकर देश से इस बर्बरता को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार को दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी पड़ेगी तभी देश के आंतरिक विकास की गति तेज होगी और भारत मजबूत देश के रूप में अतंर्राष्ट्रीय मंच पर सशस्त्र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हो सकेगा।

lnHkZ&

1. योजना– फरवरी 2007
2. इंडिया टुडे– 13 फरवरी, 2008
3. नई दुनिया– जुलाई, 2008
4. रिपोर्ट– केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार
5. टी.वी. न्यूज चैनल